



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला-सिंगरौली

III/भू-राजस्व/सिंगरौली/श्रृंखला/2017/4265

श्री न्यायालय
द्वारा आज दि ३.११.१७ को
प्रस्तुत

विरुद्ध
राजस्व मण्डल भू-राजस्व

क्रमांक १७.११.१७

- 1- मुदसिसर हुसैन पुत्र श्री गुलाम अहमद
- 2- मुजबिर हुसैन पुत्र श्री गुलाम अहमद
- 3- मुजविकर हुसैन पुत्र श्री गुलाम अहमद
- 4- सोनू मोहम्मद पुत्र श्री गुलाम अहमद
- 5- मुजस्सिम हुसैन पुत्र श्री गुलाम अहमद
- 6- मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री गुलाम अहमद
निवासीगण- लदवई तहसील सरई जिला
- सिंगरौली (म.प्र.)

-- आवेदकगण

विरुद्ध
म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला
सिंगरौली (म.प्र.)

-- अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार तहसील सरई द्वारा प्रकरण क्रमांक

7/अ6अ/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2017 के विरुद्ध
म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान

हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहांकि, ग्राम लदवई में स्थित आराजी खसरा क्रमांक पुराना 2 मिन रकवा 5.504 है0, 3 मिन रकवा 2.023 है0, 4 मिन रकवा 0.850 है0, 6 मिन रकवा 2.023 है0 कुल किता 4 कुल रकवा 10.400 है0 का मूलतः पट्टा आवेदकगण के माता जैबुनिशा पुत्री कासिम खाँ के नाम वर्ष 1958-59 के वार्षिक खतौनी एवं खसरा वर्ष 1956-57 से लगातार 1960-61 से लगायत 1974-75 तक के पुराने अभिलेखों में दर्ज भूमि स्वामी अभिलेख था। जो सहवन गत् वर्ष 1975 में म.प्र. शासन अंकित किया गया था जिसका खसरा सुधार हेतु माता जैबुनिशा पुत्री कासिम खाँ के द्वारा तहसीलदार सिंगरौली प्रभारी माडा में आवेदन पत्र पेश किया गया जो प्रकरण क्रमांक 15/अ6अ/1974-75 पर पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 06.07.1976 से स्वीकार किया गया। जिसके

(64)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुबत्ति आदेश प्रष्ट

प्रकरण क्रमांक III/३०१/८०१/२०१/१४/४२६५

३३१२-२१८/७०८८८

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
---------------------	--------------------	--

०९/०१/१९

आवेदक की ओर से श्री एम्प्लायमेंट अधिवक्ता
द्वारा यह निगरानी तहसीलदार - मृदु के
प्रकरण क्रमांक ७/३२-६-३४/१६-१८ में पारित आदेश दिनांक
२६-१०-१८ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में
दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित
संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु
प्रकरण कलेक्टर जिला - मृदु के न्यायालय को अंतरित किया
जाता है। उभय पक्ष दिनांक २२/४/१९ को कलेक्टर जिला
मृदु के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।

सदस्य